माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण

1. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे आप सबको सम्बोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस वर्ष के पहले सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा के 8वें सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

2. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 25 दिसम्बर, 2012 को सत्ता संभाली तथा तभी से कड़ी मेहनत कर सरकार ने इन दो वर्षो की अवधि में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया गया तथा इसमें किए गए अधिकांश वायदों को मेरी सरकार द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया है।

3. मेरी सरकार शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दे रही है, तथा प्रदेश में सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरकार ने गत दो वर्षो में 100 नए प्राथमिक स्कूल खोले तथा 160 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। विगत दो वर्षो में 6 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 7.74 करोड़ रुपये की धन राशि व्यय की गई । पहली से 8वीं कक्षाओं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर 15.6 करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

4. प्रदेश में शैक्षणिक स्तर में सुधार की वचनबद्धता के अनुरूप, मेरी सरकार ने पैरा अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किया है। 10 वर्षो का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 684 टीजीटी तथा 695 सी एण्ड वी पैरा अध्यापकों की सेवाएं नियमित की गई हैं। इसी प्रकार पी.टी.ए. अध्यापकों को अनुबंध पर लाने के निर्णय को कार्यान्वित किया गया है । अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने गत दो वर्षो में 1292 टी.जी.टी., 728 सी एण्ड वी तथा 1177 जे.बी.टी. अध्यापकों की नियुक्ति की तथा 276 जे.बी.टी. को टी.जी.टी. तथा 25 जेबीटी को एल.टी. में पदोन्नत किया है।

5. मेरी सरकार ने गत दो वर्षों में 234 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च तथा 225 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 14 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। वर्ष 2014–15 की अवधि में उच्च पाठशालाओं के लिए 788 पद तथा नई स्तरोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए 1260 पद सृजित किए गए हैं।

6. अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 2014 तक शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ की 954 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा तथा 905 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी गई हैं। जनवरी, 2015 में 1733 पी.टी.ए. प्राध्यापकों/डी.पी.ई. की सेवाओं को पी.जी.टी./डी.पी.ई. के रूप में अनुबंध आधार पर लिया गया है तथा 591 पैरा प्राध्यापकों/डी.पी.ई. को नियमित किया गया है।

7. उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 11 राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 412 छात्रों में 50.89 लाख रुपये की राशि वितरित की गई । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 13692 छात्र केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित हुए तथा इस पर 30.21 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई ।

8. मेरी सरकार पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। यह सुविधा नवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आई.आर.डी.पी. श्रेणी के छात्रों को भी उपलब्ध हैं। इस पर इस वर्ष 9.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं तथा 1 लाख 16 हजार 924 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

9. महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत नवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को वर्दी के दो जोड़े निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं। इस पर 2014–15 के दौरान 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

10. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अन्तर्गत सत्र 2013–14 से प्रदेश की 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यवसायिक शिक्षा

आरम्भ की गई है। वर्ष 2014–15 में 100 अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में इसे सात विषयों/ट्रेड में आरम्भ किया गया है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण सहभागियों द्वारा 600 व्यवसायिक अध्यापकों/प्रशिक्षकों को तैनात किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 20 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं।

11. मेरी सरकार ने 2013–14 से ही 90 तथा 10 प्रतिशत अनुपात में वित्त पोषित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया है। सरकार ने शिक्षा गुणात्मक सुधार प्रणाली लागू करने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है। सरकारी, निजी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में समेस्टर प्रणाली तथा विकल्प आधारित आकलन प्रणाली आरम्भ की है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2014–15 के लिए 8.85 करोड़ रुपये अनुदान की पहली किश्त जारी कर दी गई हैं।

12. वर्ष 2014–15 के दौरान तकनीकी संस्थानों में कुल 36 हजार 633 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में तकनीकी संस्थानों में प्रति लाख जनसंख्या पर सीटों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगस्त, 2013 से समेस्टर तथा ओ.एम.आर. परीक्षा प्रणाली लागू की गई हैं। प्रदेश में सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं की 6 हजार 192 सीटें उपलब्ध हैं।

13. राजकीय पॉलटेक्निक सुन्दरनगर में दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त 2014 से सामुदायिक कॉलेज शुरू किया गया है। डिप्लोमा धारकों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त, 2014 से तीन महीने के लिए दो घंटे प्रतिदिन की अवधि का सम्प्रेषण दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल आरम्भ किया गया है।

14. मेरी सरकार समाज के उपेक्षित तथा कमज़ोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन तथा महिलाओं व बच्चों को समय पर लाभ प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण के लिए 103.24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

15. प्रदेश में 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण कम करने तथा बच्चों व महिलाओं में अनीमिया में कमी लाने के लिए

'एकीकृत बाल विकास योजना' को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने गत वर्ष में पूरक पोषाहार प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन किया है।

16. सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल, माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, विधवा पुनर्विवाह आदि जैसी योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को भी संशोधित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं के दृष्टिगत मेरी सरकार ने इनके अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

17. 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, किशोरियों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार तथा स्वास्थ्य जांच शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 4 लाख 55 हजार 289 बच्चे, 1 लाख 2 हजार 830 गर्भवती एवम् धात्री महिलाएं तथा 1 लाख 38 हजार 884 किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

18. मेरी सरकार ने राज्य बाल अधिकार आयोग को भी क्रियाशील बनाया है। यह आयोग असहाय एवं असुरक्षित बच्चों की देखभाल एवम् उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शिमला, मण्डी, कांगड़ा तथा चम्बा जिलों में चार जिला बाल सुरक्षा इकाइयां स्थापित की हैं। सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित एवम् पंजीकृत 21 बाल गृहों के माध्यम से 751 जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत देखभाल भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

19. माननीय सदस्यगणों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 235 करोड़ रुपये खर्च कर रही है । विभिन्न श्रेणियों के 3 लाख 4 हजार 921 लोगों को पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। 79 आयु वर्ग तक के पात्र लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 550 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा 80 वर्ष से अधिक के पात्र लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रथम अप्रैल, 2013 से 800 रुपये से बढ़ाकर 1000

रुपये प्रतिमाह किया गया है। 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रथम अप्रैल, 2014 से 550 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रथम अप्रैल, 2014 से 12 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी मामले निपटा लिए गए हैं।

20. सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नए आवास निर्माण के लिए 75 हजार रुपये तथा आवास की मुरम्मत के लिए 25 हजार रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे 2417 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

21. मेरी सरकार जातिवाद को हतोत्साहित करने के लिए अन्तरजातीय विवाह के लिए पुरस्कार स्वीकृत कर रही है। अन्तरजातीय विवाह अनुदान को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

22. अपंग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षुओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्टाईफंड दिया जा रहा है।

23. मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 200 या इससे अधिक जनसंख्या वाले तथा 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के दो गांवों को चयनित किया गया है। प्रत्येक ऐसे गांव को एकीकृत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 12.31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

24. सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 30 नवम्बर, 2014 तक ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 लाख 6 हजार 758 राशनकार्ड धारकों को 3 लाख 79 हजार 405 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए हैं। 4 796 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने प्रदेश के

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन शुरू की है।

25. मेरी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के 36.82 लाख लोगों को लक्षित किया गया है, जिनमें से 32.98 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें कम दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 20 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 15 किलो चावल 3 रुपये प्रतिकिलो की दर से प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध किया जा रहा है । इसी प्रकार बी.पी.एल. परिवारों को 3 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से उपलब्ध किया जा रहा है। अन्नपूर्णा एवं तिब्बती परिवारों, वृद्धावस्था पेंशनरों, अक्षमता पेंशनरों तथा कुष्ठ रोगी पेंशनरों को भी इसमें शामिल किया गया है।

26. मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रति सदस्य पात्रता के स्थान पर बी.पी.एल. परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति राशनकार्ड उपलब्ध करवा रही है। अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकार 19 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही है।

27. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के ए.पी.एल. परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गंदम आटा तथा 15 किलो चावल शामिल है, भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार, प्रदेश के अन्य भागों में रह रहे ए.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह 20 किलो खाद्यान्न, जिसमें 14 किलो गंदम आटा तथा 6 किलो चावल शामिल हैं, उपलब्ध करवाया जा रहा है।

28. मेरी सरकार राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत सभी राशनकार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा एक किलो आयोडीनयुक्त नमक प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय होगी।

29. ई.पी.डी.एस. परियोजना के अन्तर्गत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 15 लाख राशनकार्ड फार्मों को सफलतापूर्वक डिजीटाइज़ किया है, जो कुल राशनकार्डों का लगभग 88 प्रतिशत है।

30. गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, सामुदाय सशक्तिकरण, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

31. राज्य सरकार ने ग्राम सभाओं के माध्यम से बी.पी.एल. सूची की व्यापक समीक्षा की है, जिसमें से 31 हजार 311 अपात्र परिवारों को हटाया गया है और उनके स्थान पर पात्र निर्धन परिवारों को शामिल किया गया है। सरकार ने राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 1333 आवास स्वीकृत किए हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 75 हजार रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 4688 आवासों को स्वीकृत किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 321 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है तथा लगभग 4 लाख परिवारों को रोज़गार प्रदान कर 138.63 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

32. पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के लिए 65.85 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से स्वच्छता अभियान में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए लगभग 3.67 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई गई है।

33. प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से पांच ब्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान 7.84 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत कुल 8 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को 48 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

34. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के

अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए 51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत भवनों की मुरम्मत/स्तरोन्यन तथा बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर तथा शिमला ज़िलों में ज़िला संसाधन केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए 5.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश की 11 ज़िला परिषदों, 65 पंचायत समितियों तथा 2609 ग्राम पंचायतों ने पी.आर.आई.ए. अकाउंटिंग साफ्टवेयर में अपने खाते कायम करने शुरू कर दिए हैं। सभी पंचायत अभिलेखों का कम्प्यूट्रीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

35. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत इस वर्ष चम्बा तथा सिरमौर ज़िलों के लिए 33.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चम्बा ज़िले के लिए 951 कार्य/योजनाएं तथा सिरमौर ज़िले के लिए 923 कार्य/योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त 5420 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

36. मेरी सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए 15 स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है तथा अतिरिक्त 74 संस्थानों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 7 नए नागरिक अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5 स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गए हैं। प्रदेश के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में सी.टी. स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

37. चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान विशेषज्ञों सहित 400 नए चिकित्सा अधिकारी, 112 फार्मासिस्ट, 258 स्टाफ नर्स, 7 रेडियोग्राफर तथा 194 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लगभग 50 चिकित्सा अधिकारी, 73 स्टाफ नर्स तथा 200 अन्य पैरा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है।

38. प्रदेश में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में हमीरपुर, चम्बा तथा नाहन में सरकारी क्षेत्र में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में एक सुपरस्पेशियलिटी व्लॉक पूरा कर दिया गया है तथा वर्तमान में पांच विभागों में सुपरस्पशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज

शिमला में 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक सुपरस्पेशियलिटी व्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

39. चम्बा में एक नया सामान्य नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू में भी एक नया सहायक नर्सिंग मिडवाईफ्री स्कूल स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा सरकारी सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाईफ्री स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

40. आयुष उपचार प्रणाली को प्रचलित करने तथा लोगों को इस प्रणाली के बारे में अवगत करवाने के लिए 2014–15 के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 27 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें 40 हजार 919 रोगियों का उपचार किया गया। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 44 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों तथा 3 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कांगड़ा, चम्बा तथा शिमला ज़िले में तीन नए आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए, जिनके संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

41. वर्ष 2014–15 के दौरान 40 कर्मचारियों को पंचकर्मा में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से पूर्वस्नातक की सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 60 कर दी हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों के 45 नए भवन तथा आयुर्वेदिक अस्पताल का एक भवन पूरा किया गया है।

42. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा विकास में तेजी लाने के दृष्टिगत मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 70 हजार क्विंटल बीज, 186 मीट्रिक टन कीटनाशक तथा एक लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करवाए गए हैं। फसल विविधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

43. वर्ष 2014 के दौरान प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन 16.20 लाख टन होने की संभावना है। मेरी सरकार मुख्यमंत्री आदर्श गाँव योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में कृषि आधारित अधोसंरचना एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

44. इस वर्ष पॉलीहाऊस के निर्माण के लिए 111.19 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ सरकार सभी ज़िलों में डा.वाई.एस. परमार, किसान स्वरोजगार योजना कार्यान्वित कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। अभी तक चालू वर्ष के दौरान एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 421 पॉलीहाउस का निर्माण किया गया है।

45. सरकार किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। इस वर्ष 11 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई है तथा 1530 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत लाया गया है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में चार पर्यावरण नियंत्रित कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं।

46. किसानों को बिचौलियों तथा दलालों के चंगुल से बचाने के लिए फलों व सब्जियों के विपणन के लिए 53 मंडियां व उप मंडियां स्थापित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की बिक्री के बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 9 अन्य मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

47. बागवानी हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान 3000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न फलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है तथा 725 हेक्टेयर क्षेत्र को पुष्पोत्पादन व 102 हेक्टेयर क्षेत्र को मसालों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

48. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान 73 हजार 450 किसानों की सेब की फसल को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 39 हजार 559 किसानों को 8.75 करोड़ रूपये का बीमा लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश में इस योजना को सेब फसल

के लिये 17 से 35 विकास खण्डों और आम की फसल के लिए 10 से 42 विकास खण्डों तक बढ़ाया गया है। किन्नू, प्लम और आड़ू जैसे फलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

49. वर्तमान वर्ष के दौरान बागवानी तकनीकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 9474 किसानों को लाभान्वित किया गया है। लगभग 2.05 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को उत्तम गुणवता वाले फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के अन्तर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, 17.55 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को एन्टी–हेल नेटों के अधीन लाया गया है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और प्रतिवर्ष 4500 मीट्रिक टन उपज क्षमता वाली 531 वर्मी–कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की गई हैं।

50. मेरी सरकार ने सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इसी तरह, राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने को भी प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पेयजल की मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में नवम्बर, 2014 तक 517 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। दो बड़ी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं जिनमें 84.58 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना सैंज नाला से घड़ोग, घण्डल एवं साथ लगती पंचायतों का संवर्धन तथा 20.96 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, बसन्तपुर, का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

51. 50 शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और देखरेख का कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। बढ़ती आबादी के दृष्टिगत हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मशाला, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, मण्डी, मनाली और रामपुर पेयजल योजनाओं का संवर्धन यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी., जबकि नाहन और सुजानपुर पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संवर्धन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। गौड़ा में 132/33 किलोवाट विद्युत सबस्टेशन के आरंभ होने से सोलन शहर और आस–पास के गावों को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति संवर्धन हेतु 336 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।

52. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 2369 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लघु सिंचाई और 3552 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नियंत्रण क्षेत्र विकास

जल प्रबंधन के अधीन लाया गया है। 471 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण के लिए उपचारित किया गया है। 8904 हेक्टयेर भूमि के संरक्षण के लिए 922 करोड़ रुपये से स्वां तटीयकरण परियोजना और 180 करोड़ रुपये की लागत से छोंछ खड्ड तटीयकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

53. आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दिसम्बर, 2014 तक 3825.03 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने हि.प्र. मुल्य बर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एकमुश्त कर अदा करने वालों को छोड़कर प्रदेश के सभी व्यापारियों के लिए ई–सेवा उपलब्ध करवाई है।

54. बैरियरों पर भीड़ को कम करने और वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए मालवाहक वाहनों के लिए वस्तुओं की ई–घोषणा सुविधा से अब राज्य से बाहर जाते हुए एसे वाहनो को बैरियर पर रूकने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में सभी व्यापारियों को वस्तुओं की मोबाईल आधारित घोषणा की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

55. मेरी सरकार जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के साथ लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्य, जिला और उपमण्डल स्तरों पर जन समस्या निवारण समितियों का गठन किया है।

56. मेरी सरकार ने सड़क क्षेत्र को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। स्वतंत्रता के समय जहां प्रदेश में केवल 288 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था, आज प्रदेश में सड़कों की लम्बाई 33,737 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 3117 पंचायतें पहले ही सड़क मार्गों से जोड़ी जा चुकी हैं और शेष पंचायतों को भी सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्त वर्ष में 245 किलोमीटर नई सड़कों और 27 पुलों के निर्माण के साथ 54 गावों को जोड़ा गया है। 532 और 740 किलोमीटर सड़कों की क्रमशः जल निकासी और मैटलिंग/टारिंग की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 2 हजार किलोमीटर सड़कों का आवधिक नवीनीकरण पूरा किया गया है।

57. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 246 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। आर. आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत नाबार्ड ने 191 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य सड़क परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है।

58. प्रदेश सरकार पर्यटकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ग्रामीण, साहसिक, धार्मिक और विलास पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ प्रदेश में वर्ष 2004–05 में 65 लाख पर्यटकों की आमद थी, वहीं वर्तमान में यह आंकड़ा 163 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष पहुंच चुका है।

59. प्रदेश सरकार ने राज्य में समग्र पर्यटन के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सत्त पर्यटन नीति 2013 अनुमोदित की है। नीति में लघु और मध्यम अवधि की कार्य योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इसी तरह धर्मशाला तथा इसके आस–पास सत्त पर्यटन सुनिश्चित बनाने के लिए 'धर्मशाला समग्र पर्यटन कार्य योजना तैयार की गई है।

60. निजी उद्यमियों को पर्यटन इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान जो अधिकतम 50 लाख हो सकता है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजातीय एवं कठिन क्षेत्रों और पिछड़ी पंचायतों में स्थापित की जा रही नई होटल इकाइयों को 1 अप्रैल, 2013 से 10 वर्ष की अवधि के लिए विलासिता कर में छूट दी गई है। यह सुविधा 1.4.2014 से ग्रामीण क्षेत्र में नई होटल ईकाईयों को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

61. प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु उड्डयन टरबाईन फ्यूल पर लगे वैट को 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

62. युवा शक्ति के उचित मार्गदर्शन हेतु मेरी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्कृष्ठ खिलाड़ियों, पदक विजेताओं और मान्यता प्राप्त वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन बार भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत रोज़गार योजना के अंतर्गत सीधा रोज़गार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 326 उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को

रोज़गार प्रदान किया गया है, जिनमें से 38 खिलाड़ियों को वर्ष 2014–15 के दौरान रोज़गार दिया गया है। मेरी सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 109 खिलाड़ियों को 94.30 लाख रुपये के नकद पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।

63. वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धा में बॉक्सिंग में एक स्वर्ण पदक, एक रजत और दो कांस्य पदक, जुड्डो में एक रजत और 4 कांस्य पदक तथा बेडमिंटन में एक कांस्य पदक अपने नाम किये हैं।

64. राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नोडल क्लब योजना, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवा उत्सव, युवा कार्य शिविरों और युवा दिवस जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। जनवरी, 2015 में असम में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के 72 युवाओं ने भाग लिया कथक में प्रथम व सितार वादन में तृतीय स्थान अर्जित किया।

65. प्रदेश में जलाशयों और नदी तटीय क्षेत्रों में 12,427 से अधिक लोग मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश में 49 मत्स्य सहकारी समितियां हैं, जिनमें 6,284 सदस्य हैं। प्रदेश में दिसम्बर, 2014 तक 54.74 करोड़ रुपये के मूल्य की 6479.22 मिट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है।

66. मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से दुग्ध उत्पादन 1170 हजार टन, जबकि ऊन उत्पादन 1661 टन तक पहुंच गया है।

67. विकासात्मक गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 28.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 72 पद भरे गए हैं। मिल्कफेड द्वारा दूध के खरीद मूल्य में एक रुपये की बढ़ौतरी की गई है। ऊन खरीद दरों में भी 7.5 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर इसे 32.5 रुपये किया गया है। 8 पशु अस्पतालों और 51 पशु औषधालयों के सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

68. पशु चिकित्सा संस्थानों में गुणात्मक कृत्रिम गर्भाधान सेवा के लिए तरल नाइट्रोजन संयंत्र की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 6.07 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा जिला के पालमपुर और शिमला ज़िला के घनाहट्टी में आधुनिक तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

69. दिसम्बर, 2014 के अंत तक प्रदेश में 18307 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 40429 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं, जिनसे 2 लाख 84 हजार, 599 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'आमंत्रण से निवेश' की नीति अपनाई है और इसी उद्देश्य से मुम्बई, बंगलुरू और अहमदाबाद में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई, जिनमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने उद्यमियों के साथ राज्य में निवेश करने हेतु विचार–विमर्श हुआ ।

70. प्रदेश के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए मेरी सरकार द्वारा अन्य कदमों के अलावा औद्योगिक सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। यह परिषद सरकार को उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर अपना परामर्श समय–समय पर प्रदान करेगी ।

71. औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा नियमों तथा उप नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। वैधानिक स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निश्चित की जा रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों द्वारा देय स्टैम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत कटौती की गई है और साथ ही विद्युत ड्यूटी में कटौती व एफ.ए.आर. नियमों में भी ढील प्रदान की गई है। इसके अलावा, औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को भी काफी हद तक सरल बनाया गया है।

72. खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत गैर बागवानी उत्पादों के लिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, एकीकृत कोल्ड चेन स्थापित करने तथा रीफर वाहन खरीदने का प्रावधन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 31दिसम्बर, 2014 तक 116 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 11.58 करोड़ रुपये की उपदान राशि स्वीकृत की गई है।

73. अवैध खनन पर निगरानी और वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए नियम बनाए

गए हैं। इन नियमों को 43 वर्षों की लम्बी अवधि के उपरांत बदला गया है। प्रदेश सरकार ने लघु खनिजों के खनन एवं नियमन के लिए नये नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की है।

74. सन्निर्माण कामगारों के लाभ के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अभी तक 63,387 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। इन कामगारों को विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, मातृत्व/पितृत्व लाभ, पेंशन, ऋण, गृह निर्माण व उपकरण खरीदने के लिए अपंगता पेंशन, दो बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता, महिला कामगारों को वाशिंग मशीनें और साइकिलें, इन्डक्शन हीटर के लिए वित्तीय सहायता, सोलर कूकर और सोलर लैंप उपलब्ध करवाने जैसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे है।

75. श्रम विभाग में कागज़ी कार्य में कमी लाने के लिए फैक्टरियों के ऑनलाईन पंजीकरण व लाईसेंस के नवीकरण के लिए फैक्टरीज़ एक्ट 1948 के अंतर्गत ऑनलाईन फैक्टरी पंजीकरण सूचना प्रणाली विकसित की गई है। अभी तक इससे 1965 पंजीकृत फैक्टरियां लाभान्वित हुई हैं।

76. मेरी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दैनिक भोगी कर्मचारियों और अंशकालिक कामगारों के दैनिक भत्ते में प्रथम अप्रैल, 2014 से 20 रुपये प्रतिदिन व 2 रुपये प्रतिघण्टा बढ़ौतरी की गई है। कटाई एवं सिलाई अध्यापकों के भत्तों को 1600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये, जबकि गृह रक्षकों के भत्तों को 225 रुपये से बढ़ाकर 260 रुपये प्रतिदिन किया गया है। गृह रक्षकों की रैंक पे में प्रथम जून, 2014 से 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय को 1 जनवरी, 2014 से 1650 रुपये से बढ़ाकर, 1850 रुपये किया गया है। सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में प्रथम जनवरी, 2014 से 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। निश्चित चिकित्सा भत्ते को भी 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये किया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के अनुबंध राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के सहायक प्रवक्ताओं को दी जाने वाली अनुबंध राशि को 21,600 से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। जैसा कि सभी

माननीय सदस्य जानते हैं, मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कर इसे क्रियाशील बनाया है।

77. मेरी सरकार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के कल्याण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सैन्य बलों के पेंशनरों के परिवारों के लिए दोहरी पारिवारिक पेंशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 10 प्रतिशत (80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत) बढ़ौतरी की गई है। प्रदेश में पेंशनरों के लिए 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु होने पर मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन भत्ते का क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार पेंशनरों की समस्याओं के निपटारे के लिए संयुक्त परामर्श समिति का गठन किया गया है।

78. प्रदेश सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और इन संस्थानों के लिए संसाधनों के हस्तांतरण की संस्तुति के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया है।

79. मेरी सरकार ने 31 मार्च, 2014 को 6 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, अनुबंध कर्मचारियों, जिन्हें पूर्व में किसी भी अवकाश की सुविधा नहीं थी, अब विभिन्न तरह के अवकाश का प्रावधान किया गया है। 31 मार्च, 2014 को 7 वर्ष की सेवा अवधि पूरे करने वाले दैनिक भोगी कर्मियों की सेवाएं नियमित करने के संदर्भ में दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2014 तक 8 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाओं को पूर्ण कालिक देय कर्मियों/दैनिक भोगी कर्मियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

80. मेरी सरकार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने 395.47 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जनजातीय उपयोजना के लिए कुल वार्षिक योजना आबंटन का 9 प्रतिशत निर्धारित किया है।

81. जनजातीय उपयोजना का निर्माण और अनुश्रवण विकेंद्रीकृत तरीके से परियोजना सलाहकार समिति के माध्यम से किया जा रहा है। समिति का नेतृत्व स्थानीय विधायक करते हैं, जबकि इसमें हिमाचल

प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद और पंचायती राज संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। इस प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक योजनाएं बनाने में सहायता मिली हैं।

82. वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला, धर्मशाला और मण्डी में तीन महिला पुलिस थाने खोले हैं, जिन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने दो पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में स्तरोन्नत किया है और चार नई पुलिस चौकियां भी खोली गई हैं।

83. सामुदायिक पुलिस योजना की 'समर्थ योजना' के अंतर्गत नवीं व दसवीं कक्षाओं की रिकॉर्ड 82 हजार 943 छात्राओं को निशस्त्र प्रतिरोध प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

84. अपराध एवं अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इसके एक बार पूरी तरह क्रियाशील होने पर सभी पुलिस थाने और गृह विभाग के अन्य कार्यालय एक दूसरे से ऑनलाईन जुड़ जाएंगें। यह प्रणाली शिमला शहर के पांच पुलिस थानों में पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

85. 'वेतन अर्जन योजना' के अंतर्गत जेलों में बंद कैदियों को रिहाई के उपरांत उनके पुनर्वास और रोज़गार प्राप्त करने के लिए विभिन्न ट्रेडों जैसे कपड़ा, कंबल, टाटपट्टी, शौलें, दरी बुनना, कारपेंटरी और सिलाई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

86. मेरी सरकार ने प्रदेश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार उन्मुलन का निश्चय किया है और भ्रष्टाचार के विरूद्ध 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में सरकारी धन के रिसाव का पता लगाने का दायित्व दिया गया है। ब्यूरों को निजी व्यक्तियों के साथ–साथ सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध मामले की जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

87. जन साधारण द्वारा ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाने को सुविधाजनक बनाने के लिए 19 सितम्बर, 2014 से टॉल फ्री नंबर– 0177–2629893 क्रियाशील किया गया है। 'एंटी करप्शन हेल्पलाईन'

के रूप में टॉल फ्री हेल्पलाईन नंबर '1064' को भी आरंभ किया गया है।

88. प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए एक राज्य स्तरीय अग्नि प्रशिक्षण केंद्र, 22 अग्निशमन स्टेशन और 9 अग्नि शमन चौकियां क्रियाशील हैं। वर्ष 2014 के दौरान श्री नैना देवी जी में एक नई अग्नि शमन चौकी स्थापित की गई है। कुल्लू ज़िले के बंजार के लारजी में स्थापित होने वाली अग्निशमन चौकी को शीघ्र ही क्रियाशील बनाया जा रहा है। काला अम्ब में भी अग्निशमन चौकी स्थापित की जा रही है।

89. मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों की वित्तीय सहायता को 750 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया है। सेना/नौसेना/वायुसेना मैडल एवं मेन्शन–इन–डिस्पैच मैडल धारकों की वार्षिकी को मु0 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। इसी तरह सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक/उत्तम युद्ध सेवा पदक/युद्ध सेवा पदक/विशिष्ट सेवा पदक से पुरस्कृत प्रतिष्ठित पदक विजेताओं की वार्षिकी को संशोधित करके प्रथम अप्रैल, 2014 से 3000 से 4000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं/आश्रितों को सात करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। सैनिक कल्याण के उप–निदेशक के अनुबन्धित वेतन को 15,700 रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। सैनिक कल्याण विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर निदेशक का एक पद और अनुबन्ध आधार पर उप–निदेशकों के आठ पद भरे जा रहे हैं।

90. मेरी सरकार पूरे प्रदेश में निर्बाध और गुणात्मक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 27436 मैगावाट जल विद्युत क्षमता में से कुल 9432 मैगावाट क्षमता का दोहन किया जा चुका है। इसमें से 490 मैगावाट बिजली राज्य क्षेत्र, 6840 मैगावाट केन्द्र व संयुक्त क्षेत्र तथा 1862 मैगावाट निजी क्षेत्र में उत्पादित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 245 मैगावाट बिजली का उत्पादन लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 956 मैगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन शुरू हो जाएगा।

91. सुरक्षा पहलुओं के अनुश्रवण के लिये 'बांध सुरक्षा राज्य प्रकोष्ठ' क्रियाशील बनाया गया है।

92. राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में वित्तीय पुनर्निमाण योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 को अधिनियमित किया गया है।

93. मेरी सरकार 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से चिन्हित 1500 मैगावाट क्षमता के तीव्र दोहन के लिये वचनबद्ध है। अभी तक, 1223 मैगावाट क्षमता की 476 विद्युत परियोजनाएं आबंटित की जा चुकी हैं। इनमें से 221 मैगावाट क्षमता की 59 परियोजनाएं क्रियाशील हो चुकी हैं। इसके अलावा, इस वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में 23.70 मैगावाट क्षमता की छः परियोजनाएं क्रियाशील की गई हैं। 18 मैगावाट की अन्य चार परियोजनाओं को इस वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

94. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग के लिये 7410 सौर फोटोवॉल्टिक स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई हैं। हिमऊर्जा द्वारा 90 किलोवाट क्षमता के 45 सौर फोटोवॉलटिक पावर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। विभिन्न लाभार्थियों को 2 लाख 71 हजार 200 एल.पी.डी. क्षमता के सौर वाटर हीटर उपलब्ध करवाए गए हैं।

95. प्रदेश में वर्तमान में 4759 विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं कार्यरत है जिनमें 15.25 लाख सदस्य तथा 259 करोड़ पूंजीभाग एवं 15340 करोड़ रुपये की पूंजी जमा है। ये संस्थाएं विभिन्न योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड–डे–मील, रासायनिक खादों व कृषि उपकरणों का वितरण 2400 विक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रभावित ढंग से कार्यान्वित कर रही हैं।

96. बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर ज़िलों में 35.47 करोड़ रूपये की परिव्यय एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 84.71 करोड़ रुपये की तीन नई परियोजनाएं शिमला, कांगड़ा और कुल्लू ज़िलों के लिये स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 16.88

करोड़ रुपये की धनराशि कार्यान्वयन एजेन्सियों को जारी कर दी दी गई हैं।

97. राज्य सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में पुनरूत्थान, सुधार एवं पुनर्गठन पैकेज को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान योजना के अन्तर्गत एक साथ 101 सहकारी सभाओं को शामिल किया गया है और 3.92 करोड़ रुपये के ऋण दावों को माफ करने के लिये अन्तिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त, बुनकर सभाओं को 3.21 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं।

98. सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगन्तुकों और कलाकारों को लाभान्वित करने के लिये ऊना ज़िला के समूरकलां में आवश्यक अधोसंरचना सहित बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना पर 1.75 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

99. हिमाचल प्रदेश में मन्दिरों की एक समृद्ध धरोहर है। स्थानीय देवता हमारी देवभूमि के अभिन्न हिस्सा है। राज्य के अनेक मन्दिर इसलिए आय से वंचित हो गए थे, क्योंकि इनकी भूमि मुजारों को निहित हो गई थी । राज्य सरकार ने अब इन मन्दिरों में नित्य पूजा–अर्चना के कार्यों में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये 5 करोड़ रुपये के रिवालविंग फंड का सृजन किया है।

100. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐतिहासिक नगरी शिमला में सांस्कृतिक सक्रियता लाने तथा गेयटी थियेटर परिसर को गुणात्मक सांस्कृतिक एवं नाट्य गतिविधियों के लिए एक प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए 'शिमला सेलिब्रेट्स' शीर्षक से गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया गया है। यह गतिविधियां शिमला के 150 वर्ष के होने के साथ भी सम्बद्ध करती है।

101. विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध करवाने के लिए मेरी सरकार ने इस वर्ष के दौरान आर.आई.डी. एफ. के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति लक्ष्य को 500 करोड़ से बढ़ाकर 765 करोड़ रुपये किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़कों व पुलों, लघु

सिंचाई, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के 765 करोड़ रुपये की 100 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

102. मेरी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान इन पिछड़े क्षेत्रों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

103. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश का उत्कृष्ट रिकार्ड है। इस कार्यक्रम की प्रगति की राज्य, ज़िला और ज़िले से निचले स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है।

104. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के चार्टर में निहित कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में कौशल स्तरोन्नयन परिषद स्थापित की गई है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास और श्रम एवं रोज़गार विभागों द्वारा कौशल प्रशिक्षण मुख्य रूप से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार बेरोज़गार युवाओं को उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास भत्ता भी प्रदान कर रही है। वर्ष 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 5 लाख युवाओं के कौशल विकास के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 तक 1.30 लाख का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान करीब एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

105. मुझे माननीय सदस्यों के साथ यह सांझा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य आय अग्रिम आक्कलनों के आधार पर वर्ष 2013–14 के लिए राज्य की वृद्धि दर को 6.2 प्रतिशत आंका गया, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर का यह आक्कलन 4.9 प्रतिशत है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013–14 के लिए 92,300 रुपये आंकी गई, जो वर्ष 2012–13 में 83,899 रुपये थी। इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 74,920 रुपये रही है।

106. प्रदेश में 52 लाख पशुओं के चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 208 हैक्टेयर वन भूमि पर पशु चारे की प्रजातियों का रोपण किया गया है। राज्य में बन्दरों की

समस्या से निपटने के लिये 18 जनवरी, 2015 तक 91,468 बन्दरों का बंधीयकरण किया गया है। राज्य में एक लाख से अधिक आबादी को लाभ पहुंचाते हुए 775 गांवों को वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों से बाहर किया गया है।

107. लेन्टाना घास का फैलाव प्रदेश में विकराल रूप धारण कर रहा है तथा लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर वन भूमि इससे प्रभावित है। लेन्टाना चरागाहों में फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों तथा गद्दी एवं गुज्जर समुदायों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रभावित क्षेत्रों को लेन्टाना मुक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 के दौरान 16 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके दस हजार हेक्टेयर वन भूमि से लेन्टाना मुक्त किया गया ।

108. वर्ष 2014–15 के दौरान 10 करोड़ रुपये के निवेश से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किये गए हैं। 518 हेक्टेयर वन भूमि पर तीन करोड़ रुपये के निवेश से मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य किये गए हैं।

109. ऊना ज़िले की 96 पंचायतों में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जाईका) द्वारा वित्त पोषित 22 करोड़ रुपये की लागत से स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना का वर्ष 2014–15 के लिए कार्यान्वयन किया जा रहा है।

110. सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों/शहरों और तेजी से विकसित होते क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1977 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इससे सुनियोजित मौसम बदलाव के अनुरूप आपदा प्रबन्धन युक्त पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील शहरी बस्तीयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा । इसके अनुसार प्रदेश में 12 नये योजना क्षेत्रों की स्थापना की गई है।

111. सरकार ने प्रदेश में स्टैम्प डियुटी एवं पंजीकरण फीस को एकत्र करने के लिए ई–स्टैंपिंग प्रणाली/ ई–पंजीकरण फीस प्राप्ति प्रणाली को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की 85 तहसीलों व उप तहसीलों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है।

112. राज्य सरकार यात्रियों के लिए गुणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और आरामदेह परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ रोज़गार एवं राजस्व सृजन के लक्ष्य को लेकर कार्य रही है। सड़क सुरक्षा और आपातकाल के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से करीब साढ़े चार लाख लोग अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं।

113. नई हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोज़गार परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं, बेरोज़गार चालकों एवं परिचालकों की सहकारी समितियों तथा विधवाओं को मिनी बसों के रूट परमिट दिए जा रहे हैं।

114. परिवहन विभाग ने परिवहन उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्टरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर विशेष बल देते हुए 10 वर्षों के अंतराल के बाद परिवहन नीति 2014 को अधिसूचित किया है।

115. परिवहन विभाग ने वाहनों की आवाजाही को अनुशासित करने के अतिरिक्त विभिन्न सड़क प्रयोगकर्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के उददेश्य से ध्वनि प्रसार प्रणाली तथा सड़क सुरक्षा जिंगल से युक्त तीन इन्सेपटर वाहनों की तैनाती की गई है।

116. हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस फ्लीट को बढ़ाने के लिए 510 नई बसें खरीदी हैं। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 800 और बसों को शामिल किया जा रहा है।

117. 'स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चैंज' को अंतिम रूप दिया गया है और इसे राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

118. प्रदेश सरकार को हरित आवरण और सतत विकास के लिए विश्व बैंक से 100 मिलियन डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और खेतीबाड़ी प्रणाली में प्रभावी तकनीकीकरण उत्थान लाने एवं जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज को नया रूप देने के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है।

119. मेरी सरकार अपने नागरिकों को घर–द्वार पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये सूचना एवं संचार तकनीक का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सर्विस डिलीवरी गेटवे के माध्यम से 11 विभागों की 38 सेवाओं को ऑन–लाईन किया गया है। राज्य में न्यायालयों और जेलों के मध्य वीडियो कान्फ्रसिंग उपलब्ध करवाने के लिये ई.–पेशी सेवा आरम्भ की गई है।

120. सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिये प्रथम चरण में ई.–कार्यालय प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिप्पा, कोषागार विभाग, पुलिस, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभागों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यू.आई.डी. परियोजना के तहत 98 प्रतिशत आबादी का नामांकन किया जा चुका है, और 96 प्रतिशत आधार नम्बरों का सृजन किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश मनरेगा में 'सीधा लाभ हस्तांतरण' करने वाला देश का पहला राज्य है। लाभार्थियों के आधार से सम्बद्ध बैंक खातों में 54.07 करोड़ रुपये की राशि का सीधा हस्तांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

121. प्रदेश के लोगों को उनके कल्याण के लिये कार्यान्वित की जा रही नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा नई तकनीकों को अपनाया गया है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने 'मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफार्म' के माध्यम से नई वर्चुअल मीडिया इकाई स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों व समाचारों की सुगम पहुंच के लिये मोबाईल फोन एप्लीकेशन को भी आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार के विकास प्रयासों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये 'हिमाचल विकास डायरी' का प्रसारण किया जा रहा है।

122. राज्य के दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे जानकारी प्रदान करने के लिये नवीनतम तकनीक, एलईडी, ध्वनि प्रसार यन्त्रों इत्यादि से सुसज्जित एक मल्टी मीडिया मोबाईल वैन को आरम्भ किया गया है।

123. शहरी स्थानीय निकायों को इस वर्ष के दौरान 70.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। एकीकृत आवास एवं स्लम बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, परवाणु, बद्दी, नालागढ़, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट के लिये 52.83

करोड़ रुपये की आठ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। योजना के अन्तर्गत 402 आवास इकाईयों का निर्माण पूरा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रदेश के 10 ज़िलों के मुख्यालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

124. शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत छोटे व मध्यम शहरों के लिये भारत सरकार ने जलापूर्ति व मल निकासी की 18 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। शहरी अधोसंरचना नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत 13 शहरों के लिये 406 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

125. शिमला के कृष्णानगर स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास के लिये 34 करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 300 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा रहा है।

126. सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों की मल निकासी योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

127. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा और इसकी विभिन्न समितियों में पेपर लैस कार्य सुनिश्चित करने के लिये 4 अगस्त, 2014 से ई–विधान प्रणाली आरम्भ की गई। इससे पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त सालाना 15 करोड़ रुपये की बचत होगी। मैं, इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विधान सभा के माननीय अध्यक्ष व स्टाफ के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

128. मेरी सरकार की गत दो वर्षों की उपलब्धियों पर मैंने संक्षेप में प्रकाश डाला है। हमें अपने लोगों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिये अभी और अधिक प्रयास करने है। हमारे प्रयासों की हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी सराहना की गई है। बहुत कुछ हासिल कर लिया गया है और अभी अनेकों मील पत्थर स्थापित करने बाकी हैं, जिसके लिये सतत् प्रयासों की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार इस खूबसूरत प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

Hon'ble Mr. Speaker and Hon'ble Members,

1. I am privileged to make this address as Governor of Himachal Pradesh. I extend greetings to all the people of the State. I also welcome you all to the first assembly session of this year and the eighth session of 12th Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

2. Hon'ble Members, my Government assumed office on December 25,2012, since then, it has been working hard and has made remarkable achievements during a spell of two years. The election manifesto of the Congress Party was adopted as a policy document and most of the promises made there-in have already been fulfilled.

3. My Government has given high priority to education as it is determined to provide access of education to all children of the State. Towards this end, Government has opened 100 new and upgraded 160 primary schools to the level of middle school during the past two years. An amount of Rs. 7.74 crore has been spent on six scholarship schemes to benefit the students in the past two years. An amount of Rs. 15.6 crore has been spent for supplying free text books to the students of all categories from 1st to 8th classes.

4. In pursuance of the commitment to improving educational standards, my Government has regularised the services of PARA teachers. As many as 684 TGTs and 695 C&V PARA teachers who have completed 10 years of service have been regularised. Similarly the decision of bringing the PTA teachers into contract has also been fulfilled. To meet the shortage of teaching staff, Government has appointed 1292 TGTs, 728 C&V and 1177 JBTs teachers in last two years and given promotion to 276 JBTs to TGTs and 25 JBTs to LTs.

5. My Government has upgraded 234 Middle Schools to the level of High Schools and 225 High Schools to Senior Secondary Schools during

the last two years. Besides, 14 new colleges have been opened in the State. As many as 788 posts for high schools and 1260 posts for newly upgraded Sr. Secondary Schools have been created during the year 2014-15.

6. To meet the requirement of teachers and other staff 954 vacancies of teaching and non-teaching staff have been filled by direct recruitment and 905 by promotion till December, 2014. In the month of January, 2015, the services of 1733 PTA provided lecturers/DPEs were taken over as PGT/DPE on contractual basis and 591 Para Lecturers/DPEs have been regularised.

7. Under higher education an amount of Rs. 50.89 lakh was disbursed among 412 students under 11 State sponsored Scholarship schemes. Besides this, 13,692 students belonging to Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Minority categories have benefitted under centrally sponsored scholarship schemes on which Rs. 30.21 crore was spent during the year.

8. My Government has been providing free text books to all students from class 1 to class 8. This facility is also available to the students of SC, ST, OBC and IRDP categories studying in 9th and 10th classes. During the year Rs. 9.93 crore have been spent for this purpose and 1,16,924 students have benefited.

9. Under the Mahatma Gandhi Vardi Yojna, two sets of uniform are being provided free to all the students studying in class 9th and 10th. For this purpose, Rs. 14 crore have been spent during 2014-15.

10. Vocational Education under National Skill Qualification Framwork has been started in 100 Senior Secondary Schools from the 2013-14 session and further 100 Senior Secondary Schools from 2014-15 with 7 subjects/trades. Under the scheme, 600 vocational

teachers/trainers have been deployed by the different Vocational Training Partners. About 20,000 students have been enrolled in this programme.

11. My Government has implemented the Rashtriya Ucchtar Shiksha Abhiyan in the State on the 90:10 funding pattern since 2013-14. The Government has constituted State Higher Education Council to implement the quality improvement system. The semester system and Choice Based Credit System has been introduced for the under graduate classes in the Government, Private, Government-aided and Sanskrit Colleges. The first instalment of grant for the year 2014-15 amounting to Rs. 8.85 crore has been released to all higher educational institution.

12. A total of 36,633 students were enrolled in technical institutions in the year 2014-15. The number of seats available in technical institutions per lakh population in the State is higher than the national average. Semester System and OMR Examination have been introduced with effect from August, 2013. Also 6192 apprentice seats are available in Government and Private Establishments in the State.

13. A community college has been made functional from August 2014 at Government Polytechnic Sundernagar under Skill Development training programme. For the enhancement of employability of Diploma holders, “Communication Skill Training Module” of 2 hours/day duration of training for 3 months has also been started in this institute since August, 2014.

14. My Government is also strongly committed to the welfare of the underprivileged and weaker sections of the society, particularly women and children. During the financial year 2014-15 for proper implementation of the schemes and providing timely benefit to women and children, my Government has kept a budgetary provision of Rs.103.24 crores for women empowerment and welfare of the children of the State.

15. The Integrated Child Development Scheme is being implemented in Mission Mode to reduce the percentage of undernourished children in the age group of 0-3 years and reduce the incidence of anaemia in children and women. My Government has revised the norms for providing supplementary nutrition last year.

16. The Government has also revised the income limit for getting financial assistance under the schemes like Mukhya Mantri Kanyadan Yojna, Beti Hai Anmol, Mata Shabri Mahila Sashaktikaran Yojna, widow remarriage etc. The State Government has increased the additional honorarium by 50% of Anganwari Workers and helpers in the State in view of the multifarious duties performed by these workers.

17. For overall development of children in the age group of 0-6 years, adolescent girls and expectant and nursing mothers, the Government is providing an integrated package of services which includes pre-school education, supplementary nutrition and health check-up under ICDS programme. During the current financial year, under this scheme a total of 4,55,289 children, 1,02,830 pregnant and lactating women and 1,38,884 adolescent girls were benefitted.

18. My Government has also made the State Child Rights Commission functional so that children in need of care and protection are provided all support and are drawn to the mainstream of society. The Government has set up four District Child Protection Units in Shimla, Mandi, Kangra and Chamba districts during the current financial year. The Government has provided institutional care to 751 children in need of care and protection through 21 registered Children Homes run by the Government as well as by NGOs.

19. Hon'ble Members will be happy to know that my Government is spending Rs. 235 crore on social security pensions during the current financial year covering 3,04,921 persons of different categories under various pension schemes. The pension has been increased from Rs. 500/- to 550/- P.M in respect of the persons upto the age of 79 years and for the persons above 80 years, it has been increased from Rs. 800/- to Rs. 1000/- w.e.f. 1.4.2013. For persons with 70% and above disability, the increased pension is Rs. 750/- instead Rs. 550/- per month from 1st April, 2014. Further 12000 new beneficiaries have been added for pension from 1st April, 2014 and pendency has been liquidated completely.

20. The Government is providing Housing Subsidy @ Rs. 75000/- for new construction and @ Rs. 25,000/- for repair of house of persons belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes. 2417 such persons are being benefitted during the current financial year.

21. My Government is providing Award for Inter-Caste Marriage to discourage casteism. The grant for Inter-Caste Marriage has been increased from Rs. 25000/- to Rs. 50000/- .

22. To develop the skills of persons with disabilities, free vocational training is being provided through selected Industrial Training Institutes in various trades. Stipend at the rate of Rs. 1000/- per month is paid to such trainees.

23. Under the Mukhya Mantri Adarsh Gram Yojna, two villages in each electoral constituency with a population of 200 or above and more than 40% of Schedule Caste population are selected. Each such village is provided Rs. 10 lac for integrated development of infrastructure. An amount of Rs. 12.31 crore is being spent under the scheme during 2014-15.

24. To ensure food for all, my Government has distributed food grains to the extent 3,79,405 M.T. under APL, BPL, AAY and Annapurna Schemes to 18,06,758 ration card holders in the state up to 30th November, 2014. Essential commodities are being provided through a network of 4,796 fair price shops. The Government has also set up toll free consumer helpline for attending and redressing the grievances of consumers of the State.

25. The Government is implementing the National Food Security Act, 2013 in the whole State. Under this Act, 36.82 lac people of the State have been targeted against which 32.98 lac beneficiaries have been identified and are being provided rations at lower prices. The beneficiaries are getting 20 kg wheat @ Rs. 2/- kg and 15 kg Rice @ Rs. 3/- kg per ration card per month in case of Antyodya Ann Yojna. Similarly 3kg wheat @ Rs. 2/- per kg and 2 kg Rice @ Rs. 3/- per kg per person per month in case of BPL. Annapurna and Tibetan families, old age pensioners, disability pensioners and leprosy pensioner is also being provided.

26. My Government is providing 35 kg. food grains per ration card to the BPL families covered under National Food Security Act instead of per member eligibility. The state Government is incurring an expenditure of Rs. 19 crores per annum for this additional amount of food grains.

27. In addition, 35 Kg. food grains which includes 20 Kg. Wheat Atta and 15 Kg Rice are being provided to the APL families of Tribal areas of the State. Similarly 20 kg food grains which includes 14 Kg. Wheat Atta and 6 Kg Rice per month is being provided to all the APL families residing in the other areas of the State.

28. My Government is committed to provide 3 dals, 2 edible oils and one Kg. Iodised salt to all the ration card holders at the prescribed scale under the State Subsidy Scheme. In the current financial year, expenditure of more than Rs. 200 crore will be incurred in this respect.

29. Under the ePDS project, the Food and Supplies Department has successfully digitized more than 15 lakh Ration Card forms, which is about 88% of total Ration Cards.

30. Eradication of poverty, employment generation, community empowerment, development of human and other economic resources in the rural areas are the priorities of my Government. To achieve this, various programmes of rural development are being implemented by the State Government.

31. The State Government has conducted a comprehensive review of the BPL list through the Gram Sabhas in which 31311 in-eligible families were excluded and replaced by eligible poor families. The Government sanctioned 1333 houses under Rajiv Awas Yojana under which financial assistance of Rs. 75000/- per unit is being given to the beneficiaries. Beside this, 4688 houses have also been sanctioned under Indira Awas Yojana during this year. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, funds to the tune of Rs. 321 crores have been utilized and 138.63 lakhs mandays have been generated by providing employment to nearly four lakh household.

32. To implement Solid and Liquid Waste Management at the gram Panchyat level, Rs. 65.85 crore has been provided. In addition, the involvement of all stakeholders in the sanitation campaign through various reward schemes is being ensured. An incentive amount of Rs. 3.67 crore has been provided for this purpose.

33. The National Rural Livelihood Mission is being implemented in a phased manner in 5 Blocks of the State. For the current year, annual action plan of Rs. 7.84 crore has been approved. Total 8000 women Self Help Groups are proposed to be provided credit of Rs. 48 crore.

34. My Government is committed to strengthen the Panchayati Raj institutions for which Rs. 51 crores have been sanctioned under the Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan for the year 2014-15. In addition, Rs. 5.08 crore has been sanctioned for repair/up gradation of Gram Panchayat buildings and construction of District Resource Centres buildings in Bilaspur, Kangra, Kinnaur and Shimla districts. 11 Zila Parishads, 65 Panchayat Samitis and 2609 Gram Panchayats have started maintaining their accounts in the PRIA Soft accounting software. All panchyat records are proposed to be computerised.

35. Under the Backward Region Grant Fund, Rs. 33.51 crore have been allocated for Chamba and Sirmour districts during the year. 951 works/schemes have been sanctioned in Chamba district and 923 works/schemes have been sanctioned in Sirmour district. Also 5420 elected representatives and officials of Panchayats have been provided training.

36. My Government is committed to provide good healthcare facilities to the people. Towards this objective the construction of 15 Health institutions was completed and another 74 institutions is under way. In addition 7 new Civil Hospitals, 9 Community Health Centres, 31 Primary Health Centres and 5 Health Sub-Centres have been opened. CT Scan facility has been made available in eleven health institutions.

37. To make up for the shortage of doctors and para-medical staff 400 new Medical Officers including Specialists, 112 Pharmacists, 258 Staff Nurses, 7 Radiographers and 194 Technical Staff have been appointed during the year. The process to recruit 50 more Medical Officers, 73 Staff Nurses and 200 other para medical staff is in process.

38. To increase the availability of doctors in the State, it has been decided to open three new medical colleges at Hamirpur, Chamba and Nahan in Government Sector with the assistance of Central Government. A Super Specialty Block at Dr. RPGMC, Tanda has been completed and Super

Specialty facilities are functional in five departments presently. A Super Specialty Block is being constructed with an estimated cost of Rs. 150.00 crore at the Indira Gandhi Medical College at Shimla.

39. A new General Nursing Midwifery School is being established at Chamba for which Rs. 3 crore has been released. A new Auxiliary Nursing Midwifery School is also being established at Kullu. A sum of Rs. 7 crore has been released to strengthen the existing Government General Nursing and Midwifery schools.

40. To popularize and make people aware of AYUSH treatment, 27 free medical camps were organized at different locations during 2014-15 wherein 40,919 patients were treated. During the year, 44 Ayurvedic Medical Officers and 3 Homeopathic Medical Officers have been appointed through H.P. Public Service Commission. Three new Ayurvedic Health Centres have been opened in Kangra, Chamba and Shimla District for which posts of different categories have been sanctioned.

41. During 2014-15, 40 employees have been imparted training in Panchkarma. Besides this, the Government has increased the undergraduate seats at Rajiv Gandhi Government Post Graduate Ayurvedic College from 50 to 60 from the ensuing 2015-16 session. 45 new buildings of Ayurvedic Health Centres and one building of Ayurvedic Hospital has been completed in 2014-15.

42. In order to uplift living standards in rural areas and to accelerate growth, my Government has given high priority to the agriculture sector. The Government provided 70,000 quintal seeds, 186 metric tons pesticides and 1 lakh metric ton fertilizers to the farmers during the year. Under the Crop Diversification Program 4,000 hectare additional area has been brought under vegetable cultivation.

43. During 2014, the production of food grains and vegetables is expected to be 16.20 lakh tonnes. My Government has implemented the 'Mukhya Mantri Adarsh Gaon Yojna' under which agriculture related infrastructure and other programs are being implemented in one panchyat each from all Assembly Constituencies.

44. The Government has implemented "Dr. Y.S Parmar Kisan Swaarojgar Yojna" in all the districts of the State with an outlay of Rs. 111.19 crore for the construction of poly houses during the year. Under this scheme, 85% subsidy is being provided to the farmers. So far 421 poly houses within an area of 1 lakh sq meters have been constructed under this scheme in the current year.

45. The Government is providing 50% subsidy to the farmers to establish vermi compost units. During the year, 11000 vermi compost units were installed and 1530 hectare area was brought under organic farming. 4 Controlled Environment Cold Stores have been setup in the private sector in the State.

46. To protect the farmers from the clutches of middlemen and brokers, 53 markets and sub markets have been established for marketing of fruit and vegetables. As a result, farmers and horticulturists are receiving better prices from the sale of their produce. In addition, 9 other markets are under construction.

47. Horticulture is playing a very important role in the economic development of Himachal Pradesh. During the year 2014-15, around 3000 hectares additional area has been brought under different fruit crops; a further 725 hectares has been brought under floriculture and 102 hectares under spices.

48. To compensate the loss due to natural calamities to fruit crops, Weather Based Crop Insurance Scheme is being implemented in the State. During 2014-15, 73450 farmers have been covered under the scheme for

apple crop out of which 39559 farmers have been benefitted with insurance claims totalling to Rs. 8.75 crore. This scheme has been extended from 17 blocks to 35 blocks for Apple and from 10 blocks to 42 Blocks for Mango in the state. Fruit like Kinnow, Plum and Peach have also been brought under the ambit of the scheme.

49. During the year, 9474 farmers have been benefited with assistance under Horticulture Mission and Rashtriya Krishi Vikas Yojna schemes. Around 2.05 lakh square metre area has been brought under protected cultivation of high value flowers and vegetables, a favourite and remunerative activity among the farmers. Besides this, 17.55 lakh square meter area has been brought under anti hail nets. Organic farming has been promoted in the state and 531 vermin compost units having capacity to produce 4500 MT per annum have been established.

50. My Government has accorded high priority for providing clean and safe drinking water to all our citizens. Similarly priority has been accorded to extending irrigation facilities to the farmers of the State. During the year 517 hand pumps have been installed upto November, 2014 in various parts of the state to supplement the drinking water demand. Two big rural water supply schemes namely augmentation of LWSS from Sainj Nala to Gharog, Ghandal and adjoining panchyats and remodelling of GWSS Basantpur are being implemented at cost of Rs. 84.58 crore and Rs. 20.96 crore respectively.

51. The operation and maintenance of 50 Urban Water Supply Schemes is with the IPH Department. Keeping in view the increase in population, the Water Supply Schemes in Hamirpur, Sarkaghat, Dharamshala, Nagrota Bagwan, Kangra, Mandi, Manali and Rampur are being augmented under UIDSSMT while the Water Supply schemes of Nahan and Sujanpur are being augmented under State Sector. The commissioning of 132/33 KV Sub Station at Gaura has ensured stable water supply to Solan Town and surrounding villages. A project costing Rs. 336

crore for augmenting water supply to Shimla town has been posed to the Government of India for funding.

52. During the current financial year, additional area of 2369 hectares was covered under minor irrigation and 3552 hectares additional area was covered under Command Area Development Water Management. Also an area of 471 hectares was treated for flood control. To protect 8904 hectare area of land, Swan canalization project and Chhonch Khad canalization costing Rs. 922 crore and Rs. 180 crore respectively are under execution.

53. The overall revenue mobilization by the Excise and Taxation Department up to December, 2014 has been Rs. 3825.03 crore which is 17% higher as compared to the corresponding period of the previous year. The Department has also made e-service available to all the dealers of the State except those who are paying lump sum tax under the H.P.VAT Act, 2005.

54. To make the transportation of goods hassle free and to prevent congestion at the barriers, the goods vehicles with full e-declaration of goods are no longer required to stop at the barrier while exiting the State. Mobile based declaration of goods as an alternative mechanism has been made available to all dealers in the State.

55. My Government has always been committed to provide a clean, transparent and efficient administration to the public along with quick disposal of the public grievances. My government has constituted Public Grievances Committees at the State, district and sub-divisional levels.

56. My Government has always accorded high priority to the road sector. The road network in the State which was only 288 kms length at the time of independence, today stands at 33,737 kms. of the total 3243 panchayats in the State, 3117 have already been connected by road and

work is in progress to connect the remaining Gram Panchayats. During the year 54 villages have been connected by constructing 245 kms of new roads and 27 bridges. Cross drainage and metaling/tarring has been provided in 532 and 740 kms road length respectively in the year. In addition periodical renewal was completed on about 2000 kms road length in the current year.

57. Under the "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna" Rs. 246 crore for 100 road work has been sanctioned. Under its RIDF scheme, NABARD has approved projects worth Rs. 191 crore. Work on the World Bank funded State Roads Project is also progressing.

58. The Government is committed to provide all basic facilities to tourists and to encourage investment in the tourism sector. The State Government is encouraging rural tourism, adventure tourism, religious tourism and leisure tourism. From 65 lakh tourists in 2004-2005, the number of tourists visiting the State has now gone up to 163 lakh.

59. The Government had framed the Sustainable Tourism Policy, 2013 to draw a road map for development of the sustainable tourism in the State. Short and medium term action plans has been incorporated in the policy. Similarly to ensure sustainable tourism in and around Dharmshala, the 'Dharamshala Sustainable Tourism Action Plan' has been prepared.

60. In order to encourage private entrepreneurs to setup tourism units, 15% Capital Investment Subsidy subject to maximum of Rs. 50 lakhs is being provided. New hotel units being set up in tribal and hard areas as well as backward panchayats have been exempted from luxury tax for a period of 10 years w.e.f. 1st April, 2013. This concession has also been extended to all new hotel units being set up in rural areas w.e.f.1.4.2014.

61. The Government has already reduced VAT on Aviation Turbine Fuel from 5% to 1 % to help the Civil Aviation sector.

62. To channelize the youth energy in right direction my Government initiated many steps. The outstanding players, Medal winners and those who participate three times in recognized Senior National level events are being offered direct employment under 3% employment scheme. Under this scheme total 326 outstanding sports persons have been given employment so far out of which 38 were employed during 2014-15. My Government has also given Rs.94.30 lacs cash award to 109 sports persons who won medals in International and National tournaments during the year.

63. In National Level Rural Sports competition 1 Gold Medal, 2 Bronze and 1 Silver were won in Boxing, 1 Silver, 4 Bronze in Judo and 1 Bronze in Badminton during the year 2014-15.

64. To involve youth in Nation building number of schemes like Nodal Club Yojna, Youth Leadership Training Programme, Youth Festival, Youth Work Camps and Youth Day etc. have been launched. 72 youth from the state participated in National Youth Festival organized in Assam in January, 2015 and won 1st position in Kathak and 3rd Position in Sitar recitation.

65. Over 12,427 persons are engaged in fishing occupation in the state, both in reservoir and riverine sectors. There are 49 fish Cooperative Societies with a membership of 6284 person. 6479.22 metric tonnes of fish valued at Rs. 54.74 crore has been harvested till December, 2014.

66. Due to sustained efforts of my Government the milk production has reached 1170 thousand tonnes while wool production reached 1661 tonnes.

67. To give fillip to the developmental activities, Rs. 28.55 crore were sanctioned under Rashtriya Krishi Vikas Yojna. 72 posts of Veterinary Officers were filled during the year. The procurement price of milk has

been increased by Rs. 1.00 per liter by Milkfed. The wool procurement rates were also increased by 7.5% to Rs. 32.5 Steps are being taken for strengthening and construction of 51 Veterinary Dispensaries and 8 Veterinary Hospitals.

68. State-of-the-Art Liquid Nitrogen Plants are also being installed at Ghanahatti, in Shimla district and at Palampur in Kangra district at a cost of Rs. 6.07 crore to ensure timely supply of Liquid Nitrogen Gas at Veterinary Institutions for quality Artificial Insemination Service.

69. Upto end December 2014, there were 40,429 industrial units in the State with an investment of Rs. 18,307 crore which were generating employment for 2,84,599 persons. The State Government has adopted "Industry by Invitation" approach to attract investment in the state and in this endeavour Investor Meets were organised at Mumbat, Bangaluru and Ahemdabhad in which high powered committee headed by Hon'ble Chief Minister interacted with entrepreneurs.

70. To speed up the setting up of industrial units, among various other steps, an Industrial Advisory Council has been set up with participation from the industry to suggest/recommend suitable changes as per the changing economic scenario.

71. To facilitate speedy industrialization, my Government is in the process of simplifying the procedures for ease of doing business. Timelines for statutory approvals are being fixed. To incentivise the industry, 50% reduction in Stamp Duty payable by the entrepreneur, reduction in Electricity Duty and relaxation of FAR norms have been approved by the Government. Further, the procedure for land purchase for industrial use has also been considerably simplified.

72. Under the National Mission on Food Processing, food processing units, integrated cold chains for non horticulture products and Reefer vehicles are being setup in the State. Under this mission, till 31-12-

2014, a sum of Rs. 11.58 crores stands sanctioned as subsidy to 116 approved projects.

73. To check illegal and to encourage scientific mining, the Rules for Minor Minerals have been framed by the State Government. These Rules have been replaced after a gap of 43 years. The State Cabinet has also approved the New Rules for regulation and mining of minor minerals.

74. For the benefit of construction workers, the Building and Other Construction Workers Welfare Board has been constituted. The board has registered 63,387 workers so far who would be eligible for the benefits under various scheme like Rastriya Swasthaya Bima Yojna, Jan Shree Bima Yojna, Maternity/Paternity Benefit, Pension, Loan, for Construction/Purchase of Tools/House, Disability Pension, Financial Assistance for Marriage and Education of Two Children, Medical Assistance, Bicycle and Washing Machines to Women Workers, financial assistance for Induction Heaters, Solar Cooker and Solar Lamp being implemented by the Board.

75. To reduce paper work the Labour Department has developed Online Factory Registration Information System for online registration of factories and renewal of licence under Factories Act, 1948. So far 1965 registered factories have been benefitted by this.

76. My Government is committed to the welfare of its employees. It has raised the daily allowance of Daily Waged Employees and Part Time Workers by Rs. 20 per day and Rs. 2/- per hour w.e.f. 01-04-2014. The allowances for Cutting and Tailoring Teachers have been increased from Rs. 1600 to Rs. 2000 while that of Home Guards from Rs. 225 to Rs. 260 per day. The rank pay of Home Guard has also been enhanced by 20% w.e.f. 1-6-2014. Honorarium of Panchyat Chowakidar has been raised upward from Rs. 1650 to Rs. 1850 w.e.f. 1-1-2014. Dearness Allowance to all employees and pensioners has also been increased by 10% w.e.f. 1-1-2014. Also the Fixed Medical Allowance has been increased from Rs. 250 to Rs. 350.

Contractual amount of Ayurvedic Medical Officers has also been increased by 25%; that of Assistant Professors of Technical Education Department from Rs. 21600 to Rs. 35000 per month. Also as Hon'ble Members are aware, my Government has established the HP State Administrative Tribunal and has made it functional.

77. My Government has also shown deep concern for well-being of its pensioners/family pensioners. Dual family pension has been allowed to the families of Armed Forces pensioners. The Dearness Relief in respect of the State Government pensioners/family pensioners has been enhanced by 10% (80% to 90%). Pension Allowance @ 5%, 10% and 15% of basic pension/family pension on attaining the age of 65 years, 70 years and 75 years respectively has been granted to the pensioners in the State. For the first time a Joint Consultation Committee has been constituted by the Government to redress the grievances of the pensioners.

78. The State Government has also constituted the 5th State Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and Municipalities and to recommend devolution of resources to these institutions.

79. My Government decided to regularize the services of those contract appointees, who have completed 6 years of service as on 31st March, 2014. Further different kinds of leave has been allowed to contract employees who were earlier without any kind of leave. The instructions regarding regularization of the services of those daily waged/contingent paid workers who have completed 7 years of services as on 31st March, 2014 have also been issued. The Government has also decided to convert the services of such part-time workers to whole time paid workers/daily wage worker who have completed 8 years service as on 31.3.2014.

80. My Government is especially committed to the overall development of the tribal areas of the State. The Government has earmarked 9% of the total annual plan allocations under Tribal Sub-Plan with an outlay of Rs. 395.47 crore.

81. Formulation and monitoring of Tribal Sub-Plan is being done in a decentralized manner through the Project Advisory Committee headed by local MLA and members from H.P Tribes Advisory Council and Panchayati Raj institutions. This process has helped to formulate need based, realistic plans.

82. The law and order situation during the year remained peaceful in the State. The State Government has opened three All-Women Police Stations at Shimla, Dharamsala and Mandi which have started functioning. In addition, the State Government has upgraded two Police Posts to full-fledged Police Stations and four new Police Posts have also been opened.

83. Under the 'Samarth Yojna' of the community police scheme, a record 82,943 girl students of 9th and 10th standards have been provided training in unarmed combat.

84. The Crime & Criminals Tracking Network and Systems (CCTNS) project is being implemented and once fully operational, all the Police Stations and other offices would be inter-connected online. This system has already been started in five Police Stations of Shimla city.

85. Under "Wages Earning Scheme", the inmates in the prisons are being imparted skills to gain employment in various trades like cloth/ blankets/ tatpatti /shawls/durries weaving, carpentry and tailoring for their rehabilitation after their release.

86. My Government is determined to eradicate corruption from the State at all levels and has adopted the policy of zero tolerance to corruption. To achieve this objective, the State Vigilance & Anti Corruption Bureau has been entrusted to weed out corruption and also to detect

leakage of Government revenue in various Departments, Boards, and Corporations. The Bureau is empowered to investigate cases against Government servants as well as against private individuals.

87. A Toll Free Telephone No. 0177-2629893 has been made functional since 19.9.2014 for the convenience of general public to lodge complaints with the Bureau. A short code "1064" as "Anti Corruption Helpline" has also been mapped on the said "Toll Free Telephone".

88. One State level Fire Training Centre, 22 Fire Stations and 9 Fire posts, are functioning in the State to combat fire hazards. One new Fire Post at Shri Naina Devi Ji has been established during 2014.The Fire Post sanctioned for Banjaar at Larji in Kullu is being made functional shortly. A Fire Post is also being set up at Kala Amb.

89. My Government is committed for Welfare of serving soldiers, ex-servicemen and their dependents. The Government has enhanced the financial assistance to the 2nd World War Veterans from Rs. 750/- to Rs. 2000/- per month. Annuity to the Awardees of Sena/Nau Sena/Vayu Sena Medal and Mention–in-Dispatch was enhanced from Rs. 3000/- to Rs. 5000/- per annum. Similarly annuity to the awardees of Sarvotam Yudh Seva Medal/ Uttam Yudh Seva Medal/ Yudh Seva Medal/ Vashisht Seva Medal (Distinguished Award Winners) has been revised from Rs. 3000/- to Rs. 4000/- per annum w.e.f. 01-04-2014. Financial benefits amounting to Rs. 7 crore have been given to the ex-servicemen and their widows/wards under the various welfare schemes. The amount of contractual salary of Deputy Director Sainik Welfare has been substantially enhanced from Rs. 15,700/- to Rs. 35,000/- per month. One post of Director on regular basis and 8 posts of Deputy Directors on contract basis are being filled-up shortly through HP Public Service Commission in the Sainik Welfare Department.

90. My Government is providing sustainable and quality power supply to the whole State. As of now, out of total 27436 MW hydel power

potential in the State, a total of 9432 MW stands harnessed. Out of this about 490 MW is being generated in State Sector, 6840 MW under Central & Joint Sector and 1862 MW under private sector. In addition about 245 MW is being generated by small Hydel projects. During current year 956 MW additional generation has been added in the State.

91. A Dam Safety State Cell has commenced functioning to monitor the safety aspects.

92. The State Government has implemented the scheme for Financial Restructuring of H.P. State Electricity Board Ltd. and enacted the H.P. Electricity Distribution Management Responsibility Act, 2014.

93. My Government is fully committed for expeditious harnessing of the identified 1500 MW potential for Small Hydro Electric Projects upto 5 MW capacity. Till now 476 power projects with an aggregate capacity of 1223 MW have been allotted out of which 59 projects with a capacity of 221 MW have been commissioned. Apart from this, 6 projects with an aggregate capacity of 23.70 MW have been commissioned in the private sector during current financial year. Another 4 projects with 18 MW capacity are targeted to be commissioned by the end of this financial year.

94. Under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), 7410 Solar Photovoltaic Street Lights for community use have been installed. HIMURJA also commissioned 45 Solar Photovoltaic Power Plants of 90 KW capacity. 2,71,200 LPD capacity Solar Water Heating Systems were provided to various beneficiaries.

95. At present there are 4759 various types of cooperative institutions with a membership of 15.25 lakh, share capital of Rs. 259 crore and deposits of Rs. 15340 crore functioning in the State. They are effectively implementing schemes like PDS, Midday meal, distribution of fertilizers and agriculture inputs through 2400 outlets.

96. The Integrated Cooperative Development projects in Bilaspur, Hamirpur and Sirmour districts with an outlay of Rs. 35.47 crore are under implementation. Three new projects for Kangra, Shimla and Kullu districts have been got sanctioned with the block cost of Rs. 84.71 crore out of which Rs. 16.88 crore has been released to the implementing agencies.

97. The State Government has implemented the Revival, Reforms and Restructuring package for the Handloom sector. Altogether 101 cooperative societies were covered under the scheme during 2013-14 and claim of loan waivers for Rs.3.92 crore have been finalised. Further Rs.3.21 crore has been released in favour of weaver's societies.

98. To promote cultural activities, a Multiple Cultural Complex having all the necessary infrastructure is being established at Samur Kala in Una district for the benefit of visitors and artists. An expenditure of Rs. 1.75 crore is being incurred on this project.

99. Himachal Pradesh has a very rich heritage of temples. The local deities are an integral part of our Devbhoomi. Many temples in the State were deprived of income because their land vested in the tenants. The State Government has now created a Revolving Fund of Rs. 5 crore to provide financial assistance to meet expenditure in such temples for their daily archana and prayers.

100. Hon'ble Members will be happy to learn that a yearlong calendar of events was drawn up under the theme 'Shimla Celebrates' to bring cultural vibrancy to the historic city of Shimla and to develop the Gaiety Theatre complex as a nucleus platform of repute for quality cultural and theatrical events. This also co-incided with 150 years of Shimla.

101. To enhance availability of funds for MLA priority schemes, my Government has increased loan sanction target from Rs. 500 crore to Rs. 765 crore under RIDF during the year. More than a hundred projects pertaining to Roads & Bridges, Minor Irrigation, Water Supply and Flood

Protection works have been sanctioned amounting to Rs 765 crore during the year.

102. My Government is committed for all round development of all regions of the State with special attention to backward areas. For this purpose an amount of Rs. 45 crore has been provided under Backward Area Sub Plan for the development of infrastructure in these backward areas during 2014-15.

103. Himachal Pradesh has an excellent track record in respect of implementation of the 20-Point Programme. The performance is being regularly monitored at the State, district and below district levels.

104. Skill Up-gradation Council has been set-up in the State under the chairmanship of the Hon'ble Chief Minister with an objective to promote development of skills as laid down under the charter of the National Skill Development Mission. The skill training is mainly being provided by Education, Technical Education, Rural Development and Labour & Employment departments. The State Government is also giving skill development allowance to unemployed youth to enhance their employability. Against the total skilling target of 5 lakhs for the 12th Five Year Plan till 2017, the State has achieved 1.30 lakh upto 2013-14. During the current financial year, nearly one lakh youth will be trained.

105. It is heartening to share with Hon'ble Members that as per State Income Advance Estimates, the growth rate of the State has been estimated at 6.2 percent for the year 2013-14 against 4.9 percent national growth. Also the Per Capita Income at current prices now stands at Rs. 92,300 for the year 2013-14 against Rs. 83,899 for the year 2012-13, which is an increase of more than 10 percent. The Per Capita Income at the national level for the same period stood at Rs. 74,920.

106. In order to meet the requirement of pastures and grazing land for 52 lakh cattle population, 208 hectares of forest land was planted with

fodder species during the year 2014-15. To combat the problem of the monkey menace in the state, 91,468 monkeys have been sterilized upto 18.01.2015. In the rationalization exercise of wildlife areas 775 villages have been taken out of the protected area network which has benefited more than one lakh population.

107. The spread of Lantana weed is posing a potential threat in the state and about 1, 50,000 hectares forest area has been infested with this weed. It has affected the grazing lands and thereby livelihoods of the local people and the migratory Gaddi and Gujjar communities. To rehabilitate the infested areas, Lantana was eradicated in about 10000 hectares of forest land with an expenditure of Rs 16 crore in 2014-15.

108. During 2014-15, 45 lakh medicinal plants were planted with an investment of Rs. 10 crores. Also soil and moisture conservation works were carried out in 518 hectares of forest land with an investment of Rs. 3 crore.

109. Swan River Integrated Watershed Management Project aided by Japan International Cooperation Agency is being implemented in 96 Panchayats of Una district with an outlay of Rs. 22 crore for 2014-15.

110. The Government has decided to bring all the Municipal Areas/ Towns and emerging Growth Centres in the State under the ambit of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977. Master Plan for each such areas will be prepared by the end of 12th Five Year Plan. This will help in achieving planned, climate change resilient, disaster management compliant inclusive growth and environmentally harmonious development of human settlements. Accordingly, 12 new Planning Areas have been constituted in the State.

111. The Government has decided to implement the e-stamping system/e-registration fee receipt system for collection of Stamp Duty/

Registration fee in the State. Under these systems, 85 Tehsils/Sub-Tehsils of the Pradesh have been covered.

112. The State Government is working on the objectives of employment generation along with providing quality, competitive and choice transport services to passengers and increasing generation of revenue to the state. Road Safety and quick response in case of any emergency remains a top priority. approximately 4.5 lakh people are earning their livelihood through the transport sector in the State.

113. Under the newly introduced Him Gramin Parivahan Swarjgar Yojna the un-employed youth/cooperative societies of un-employed drivers/conductors and widows are being given rout permits for mini buses in rural areas.

114. The Transport Department has notified the Transport Policy 2014 after a gap of 10 years to cope up with emerging needs of transport consumers and transporters with special stress on Road safety activities.

115. The Transport Department has also launched three inceptor vehicles fitted with public address system and airing road safety jingles in order to discipline the movement of vehicles besides creation of awareness amongst various road users.

116. To upgrade its fleet of buses HRTC has purchased 510 new buses. In addition 800 more buses are being included under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission.

117. The State Action Plan on Climate Change has been finalized as a part of adaptation and mitigation strategies and has been approved by National Expert Committee.

118. The State Government received a Development Policy Loan of 100 Million dollars from the World Bank for shift towards green growth

and sustainable development. The Environment Master Plan has been finalized and Biotechnology Policy document has been reoriented and restructured towards bringing effective technological upliftment in skills and farming systems in rural areas of the State.

119. My Government is making good use of Information and Communication Technology (ICT) in order to deliver Government services at the doorsteps of its citizens. Through the Service Delivery Gateway 38 services of 11 departments have been made online. The e-Peshi service to provide Video Conference facility between courts and jails is being introduced in the State.

120. In order to bring transparency in the Government offices, e-Office system is being implemented in the first instance in I.T. Department, HIPA, Treasury department, Police and IPH Departments. Enrolment of 98% residents has been made under the UID Project, and 96% AADHAR numbers have been generated. Himachal Pradesh is among the first States in the country to start "Direct Benefit Transfer (DBT)" in MGNREGA. An amount of Rs. 54.07 crores has been successfully transferred into the Aadhaar enabled bank accounts of beneficiates.

121. With an objective to create awareness amongst the people of State about the policies and the programmes being implemented for their welfare, new technologies are being adopted by my Government. The Information & Public Relation Department has set up a new 'Virtual Media Unit' through 'Multiple Social Media Platform'. Also Mobile Phone Application has been launched for easy access to news and government releases. 'Himachal Vikas Diary' telecast has been commenced to portray development initiatives of the State Government.

122. A "Multimedia Mobile Van" duly fabricated and equipped with latest technology LED, PA equipments etc. has been started to cover the remote and inaccessible areas of the State & to disseminate information about the Government policies and programmes among masses.

123. A sum of Rs 70.4 crore has been released to various urban local bodies during the year. Eight projects have been sanctioned under Integrated Housing and Slum Development Program (IHSDP) for Hamirpur, Dharamshala, Solan, Parwanoo, Baddi, Nalagarh, Sundernagar and Sarkaghat with total allocation of Rs. 52.83 crore. 402 dwelling units have been constructed/completed under the scheme. The National Urban Livelihood Mission (NULM) is being implemented in 10 district headquarters of the State.

124. Under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT), the Government of India has sanctioned 18 projects of water supply and sewerage. Further, under the Urban Infrastructure Renewal scheme, projects have been sanctioned covering 13 towns with an approved cost of Rs. 406 crore.

125. A pilot project for re-development of Krishna Nagar Slum in Shimla amounting to Rs. 34 crore has been approved. Under this, 300 dwelling units will be constructed.

126. A sum of Rs. 28 crore is also being spent on sewerage schemes in various urban areas by the I&PH Department.

127. It is a matter of pleasure to inform the Hon'ble Members that e-Vidhan system has been started from 4th August, 2014 in HP Vidhan Sabha to ensure paperless work of the House and the various Committees of the Vidhan Sabha. Approximately Rs. 15 crore will be saved every year apart from saving the environment. I appreciate the efforts of Hon'ble Speaker and the staff of Vidhan Sabha in implementing this project.

128. The achievements of my Government in the past two years have been briefly highlighted by me. However we have a long way to go in our endeavour to achieve happiness and prosperity for our people. Our efforts have been appreciated by the World Bank in its recent report. A lot has been achieved yet many milestones are yet to be reached for which

constant efforts are needed. I assure you that my Government will meet the aspirations of the people of this beautiful State.

JAI HIND, JAI HIMACHAL